



Good Bye To Dear "Golu"

R.D. Singh managed to get down on a narrow ledge, which was a few feet above the deep flowing waters of Chambal.

Greenpeace Day

Make everyday changes in your life to help preserve the planet, or volunteer with or donate to Greenpeace to further their cause of planet salvation.

'निवेशकों ने प्रदेश की डबल इंजन सरकार पर भरोसा जताया'

मुख्यमंत्री भजनलाल ने यह भी कहा कि 5 साल में राजस्थान की अर्थव्यवस्था डबल होगी। उन्होंने कहा कि, राजस्थान में विदेशी भाषाओं की लर्निंग के लिए महाविद्यालय खोला जाएगा

जयपुर, 14 सितम्बर। राजस्थान में उद्योग-धंधों की अपार संभावनाओं के चलते निवेशकों को आमंत्रित करने दक्षिण कोरिया और जापान यात्रा पर गए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जयपुर लौटने पर आज एयरपोर्ट से लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय तक उनका भव्य स्वागत किया गया। लोक कलाकारों

मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान के लिए इन्वैस्ट समिट की तरह ग्लोबल समिट होगा और 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक नई दिल्ली में रोड शो होगा।



जापान और उत्तर कोरिया की यात्रा के बाद वापस लौटने पर जयपुर एयरपोर्ट से लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय तक मु. मंत्री भजनलाल शर्मा का भव्य स्वागत किया गया। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में मु. मंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुये कहा, जापान के निवेशकों ने राजस्थान में निवेश के विषय में बहुत ही पॉजिटिव प्रतिक्रिया दी है।

और भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगादों, बैड-बाजों के साथ पुष्प वर्षा के बीच भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अभिनंदन किया। भाजपा के कार्यकर्ताओं का अपार प्रेम, स्नेह और भरोसा देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी को धन्यवाद देते हुए यह विश्वास दिलाया कि भाजपा की सरकार प्रदेश के विकास की दिशा में नए आयाम

स्थापित करेंगी।

मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान की जनता के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं के भरोसे से मुझे कार्य

करने की ताकत मिलती है। इसी का परिणाम है कि महाराष्ट्र के बाद दक्षिण कोरिया और जापान के निवेशकों ने राजस्थान में निवेश करने के लिए पॉजिटिव प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा,

जापान की एक कंपनी ने तो राजस्थान के 15 हजार युवाओं को जापान में रोजगार तक देने का वादा भी कर दिया। ऐसे में राजस्थान में विदेशी भाषाओं की (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

अशोक गहलोत के सब्सिडी वादों के झूठे जाल में फंसे उद्योगपति

पिछली कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2022 में "रिप्स पॉलिसी" की घोषणा तो की, लेकिन नीति बनाकर टैक्स छूट व सब्सिडी नहीं दी

कार्यालय संवाददाता- जयपुर, 14 सितम्बर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछली सरकार में कोटबैंक साधने और अपनी सरकारी के लिए वाहवाही लूटने के लिए कई तरह की सब्सिडी देने का झंझा उद्योगपतियों को दिया था। इन घोषणाओं के झूठे जाल में फंसेकर जिन कंपनियों ने करोड़ों रु. खर्च करके राजस्थान में कई प्लांट लगा दिए, उनमें से अधिकांश को उनकी सरकार ने सब्सिडी ही नहीं दी।

वर्ष 2022 में गहलोत सरकार ने राजस्थान इन्वैस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (रिप्स) लागू करते समय निवेशकों को, जो टैक्स छूट व सब्सिडी राहत देने की घोषणाएं की थी, वह नहीं दी गई। क्योंकि रिप्स पॉलिसी 2022 में बनी, लेकिन इसके प्रक्रिया संबंधी दिशा निर्देश ही गत 23 अगस्त 2024 को जारी किए गए। इस गाइडलाइन के मुताबिक सब्सिडी

अब 2 साल बाद भजनलाल सरकार ने "रिप्स" में सब्सिडी व छूट देने के लिए गत 23 अगस्त 2024 को प्रक्रिया संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके पूर्व किस कंपनी को कितनी राहत, कैसे दी जाएगी, इस संबंध में कोई गाइडलाइन तय नहीं थी।

गहलोत सरकार ने "रिप्स" पॉलिसी की घोषणा के समय निवेशकों को स्टाम्प ड्यूटी, कर्नरज चार्ज, लैंड टैक्स, विद्युत शुल्क, बाजार अथवा मंडी टैक्स के साथ ब्याज सब्सिडी, टर्म लोन में राहत, ग्रीन इन्सैन्टिव, कैपिटल सब्सिडी, टर्न ओवर लिंक सब्सिडी, इन्वैस्टमेंट सब्सिडी, क्लस्टर बैनिफिट समेत कई तरह की छूट देने के वायदे किए थे।

पाने के लिए कम से कम 50 करोड़ तक का निवेश अनिवार्य रखा गया है। इसके अभाव में व्यापार विस्तार के लिए मौजूदा निवेश का 25 प्रतिशत से ज्यादा राशि लगानी होगी। या मौजूदा उद्योग की

20 प्रतिशत क्षमता बढ़ानी होगी। अशोक गहलोत की सरकार ने जब "रिप्स" पॉलिसी की घोषणा की थी, तब निवेशकों से वादा किया गया था कि (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

जुबेर खान करीब डेढ़ वर्ष से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की खबर मिलते ही मेव समाज एवं कांग्रेसजनों में शोक की लहर दौड़ गई।

सूचना मिलते ही अलवर में कांग्रेस नेताओं सहित मेव समाज में शोक की लहर दौड़ गई। उन्हें शनिवार शाम पांच बजे सुपुर्न-ए-खाक किया गया।

जुबेर खान ने 8वीं तक की पढ़ाई अलवर के माचडी गांव के पास बगड़ राजपूत स्कूल से की थी। इसके बाद अलवर शहर के नवीन सौनियर सेकेंडरी (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

चीनी कम्पनियों में निवेश कर रही थीं सेबी चीफ

जाल खंभाता- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 14 सितम्बर। कांग्रेस मीडिया चेयरमैन पवन खेड़ा ने शनिवार को सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने कहा कि माधवी ने 2017 से 2023 के बीच विदेशी फर्मों की लिस्टेड सिक्युरिटीज में निवेश किया था। उन्होंने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री को पता था कि वह ऐसे समय में चीनी कम्पनियों में निवेश कर रही थीं जब भारत चीन के साथ भू-राजनैतिक

समस्या का सामना कर रहा है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सेबी प्रमुख चीनी कम्पनियों में निवेश कर रही हैं और यह अभी भी चल रहा है उनके पास चीनी कम्पनियों की सनसनीखेज सूचनाएं हैं। खेड़ा ने आरोप लगाया कि यह चीनी सामान भारत ला रही है।

खेड़ा ने माधवी से पूछा क्या उनकी और उनके परिवार को उन कंपनियों से कोई सांतगांठ है जिनके नाम पनामा पेपर्स या पैराडाइज पेपर्स में थे।

माधवी और उनके पति ने इन आरोपों पर कानूनी कार्यवाही की धमकी दी है कि खेड़ा ने कहा कांग्रेस विपक्षी दल होने की जिम्मेवारी निभा रही है।

प्र.मंत्री मोदी के सी.जे.आई. के घर जाने पर न्यायविदों में भारी विवाद खड़ा हुआ

सुकुमार साह- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 14 सितम्बर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सी.जे.आई.) डी.वाय. चन्द्रचूड ने नई दिल्ली स्थित आवास पर हुई गणपति पूजा में जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। जाने-माने वकीलों, रिटायर्ड जजों और विपक्षी नेताओं ने इस पर कई सवाल उठाए हैं। यह भी पूछा जा रहा है कि पूजा में जाने की खबर को क्या सार्वजनिक किया जाना चाहिए था।

राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने ऑन लाइन प्रचारित हो रही वीडियो क्लिप पर आश्चर्य जताया। सिब्बल, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते 50 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, ने सी.जे.आई. की ईमानदारी और निष्ठा के प्रति पूर्ण सम्मान प्रकट किया लेकिन इस घटना के प्रचार पर चिंता जताई।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को निजी कार्यक्रमों का प्रचार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हो सकता है सी.जे.आई. का इरादा सार्वजनिक प्रचार का ना हो, पर ऐसे निजी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की उपस्थिति उचित नहीं थी।

सिब्बल ने कहा कि इस घटना को लेकर जो बातें चल रही हैं उससे सुप्रीम कोर्ट की साख पर दाग लग सकता है। प्रधानमंत्री मोदी सी.जे.आई. के आवास पर हुई गणपति पूजा में शामिल

- भाजपा के सखित पात्रा का तर्क है कि 2009 में जब तत्कालीन प्र. मंत्री मनमोहन सिंह ने इफ्तार पार्टी दी थी तब तत्कालीन सी.जे.आई. के.जी. बालाकृष्णन उसमें शामिल हुए थे, अब गणेश पूजा पर विवाद अनुचित है।
- सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का तर्क है कि प्रधानमंत्री का गणपति पूजा पर सी.जे.आई. के घर जाना व्यक्तिगत मसाला हो सकता है, पर, उसका वीडियो बनाकर प्रचारित करना सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा पर आघात है।

हुए तथा एक वीडियो में सी.जे.आई. व उनकी पत्नी को मोदी का स्वागत करते हुए दिखाया गया। इस पर विपक्षी नेता व कानूनविद तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे आर.एम. लोखं ने कहा कि संवैधानिक रूप से "शक्तियों का पृथक्करण" (सैपरेशन ऑफ पावर्स) है और आमतौर पर न्यायपालिका व कार्यपालिका के बीच दूरी रखी जाती है। उन्होंने कहा ऐसी मुलाकातों से न्यायपालिका को सार्वजनिक अवधारणा प्रभावित होती है, पर न्यायिक फैसलों पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने कहा जज जो भी स्वतंत्र रूप से करना चाहता है वो करेगा। पर मेरी याददाश्त में यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री किसी सी.जे.आई. के सरकारी आवास पर गए हों।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने कहा, यात्रा को सार्वजनिक बनाना गलत था। मेरे विचार से विजिट को सार्वजनिक करना सही नहीं था। मुझे नहीं पता किसने किसे आमंत्रित किया था पर मैं कह सकता हूँ कि ऐसे विजिट आम जनता की नजर में न्यायपालिका की छवि को प्रभावित कर सकते हैं। माथुर 2018 से 2021 तक इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने आगे कहा, मुझे नहीं लगता इससे सी.जे.आई. के भावी फैसले प्रभावित होंगे पर इससे आम जनता में उनकी गलत छवि बनेगी। इससे गलत संदेश जा सकता है।

शिवसेना (उद्धव बाल ठाकरे) के सांसद संजय राउत ने कहा कि गणपति उत्सव चल रहा है लोग एक दूसरे के घर जाते हैं मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री किसी के घर गए हैं या नहीं। दिल्ली व महाराष्ट्र सदनों में कई जगहों पर गणपति उत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री सी.जे.आई. के घर गए उन्होंने आरती की। हमें लगता है कि अगर संविधान के संरक्षक राजनेताओं से मिलेंगे तो जनता (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

जलजीवन मिशन में 22 हजार करोड़ रु. के ठेके, केवल 8-10 कम्पनियों को पूल बनाकर बांटे गए

गहलोत सरकार का पूल बनाने का मकसद था कि टैंडर भरने वाली कम्पनियों की संख्या कम से कम हो

रेणु मिश्रल- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 14 सितम्बर। बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के टैंडरों में मिलजुल कर दरें भरने और अपनी मर्जी के लोगों को न्यूनतम दर पर लाकर काम देने का खेल गहलोत सरकार में बेशर्मा से चला। जल जीवन मिशन के लगभग 22 हजार करोड़ के ठेकों में केवल 8-10 कंपनियों ने काम आपस में बांट लिए और 27 से 42 प्रतिशत ऊंची दरें भर दीं जिनको तत्कालीन ए.सी.एस. पी.एच.ई.डी. सुबोध अग्रवाल ने आंख मीचकर अनुमोदित कर टैंडर वित्त विभाग को भेज दिए, वित्त विभाग के मंत्री खुद अशोक गहलोत थे। समाचार पत्रों में मामला छपने और पाली सांसद पी पी चौधरी द्वारा लोकसभा में उठाए जाने पर गहलोत को निविदाएं निरस्त करनी पड़ी थीं।

अब प्रश्न उठता है कि पूल कैसे हो पाया और कैसे सिद्ध होता है कि गहलोत सरकार के समय पूल हुआ। ये खेल शुरू होता है इस बात से कि टैंडर भरने की योग्यता रखने वाली फर्मों कम से कम हो जिससे पर जायज, नाजायज दबाव और लालच का इस्तेमाल करके

असल में गहलोत सरकार का इरादा था कि कम्पनियों कम से कम रहें और उन पर, जायज-नाजायज दबाव डालकर तथा लालच का इस्तेमाल कर चहेती कम्पनी को ही काम दिलवाया जाए।

ऐसा कहा जा रहा है कि पूल बनाने से ठेकेदारों को 2000 करोड़ रूपए की राशि अधिक मिली, जिसका उपयोग उन्होंने नेताओं और अफसरों को खरीदने में किया।

यह मांग उठ रही है कि पूरे प्रकरण की सी.ए.जी. ऑडिट और सी.बी.आई. जांच होनी चाहिए तब ही साबित होगा कि गहलोत ने मेधा इंजीनियरिंग को काम दिलवाने के लिए पूल बनाने का खेल रचा था।

कामों का बंटवारा किया जाए। अगर ऐसे टैंडरों की ऑडिट हो तो पता चलेगा कि एक फर्म जिस टैंडर में न्यूनतम है और उसमें किसी एक आइटम की रेट 1 करोड़ ऑफर करती है तो उसी आइटम की रेट दूसरे टैंडर में (जिसमें पूल की

अन्य फर्म न्यूनतम है) 1.5 करोड़ भर देती है। ई.आर.सी.पी. का काम विशेष प्रकार का होने के कारण, एक तो इस तरह की इंफ्रा कंपनियों देश में कम ही हैं और तकनीकी योग्यता की शर्तें मेधा इंजीनियरिंग के मन माफिक रखने से विश्वराज कंस्ट्रक्शन जैसी बड़ी कंपनी भी क्वालीफाई नहीं कर पाई और क्या मालूम उस कंपनी ने दबाव में जानबूझकर पूरे कागज ही प्रस्तुत नहीं किए।

तीन पैकेजों में केवल दो फर्म, मेधा इंजीनियरिंग और रामकी इंफ्रा की दरें खुलीं और आश्चर्यजनक रूप से तीनों में से एक में भी रामकी इंफ्रा न्यूनतम नहीं आ पाई। इस तरह के प्रतिष्ठा पूर्ण प्रोजेक्ट के टैंडर की दरें जिस लापरवाही से रामकी इंफ्रा ने भरी हैं उसकी जांच अगर गहराई से होगी तो स्पष्ट हो जाएगा कि (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

सरकार ने खाद्य तेलों की इम्पोर्ट ड्यूटी में 20 प्रतिशत वृद्धि की

नयी दिल्ली, 14 सितंबर (वार्ता) सरकार ने विदेशों से मंगाये जाने वाले कच्चे और रिफाईंड खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में 20 प्रतिशत तक वृद्धि कर दी है, जिससे सस्ते तेलों के आयात पर अंकुश लगाने की उम्मीद है।

भारत के राजपत्र में वित्त मंत्रालय ने वार्तामन संकेत का समाधान ढूँढने के लिए आंदोलनरत जूनियर डॉक्टरों के केवल एक छोटे से ग्रुप को शाम को अपने घर बुलाकर डॉक्टरों के आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया।

उन्होंने हर तरह से युवा डॉक्टरों को लुभाने की कोशिश की, यहाँ तक कि उनके स्वास्थ्य के बारे में भारी चिंता भी व्यक्त की। चूँकि, इन दिनों शहर में लगातार बारिश हो रही है, मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों को "नहीं मींगने" की सलाह दी।

ममता बनर्जी थक हार कर आन्दोलन स्थल पर भी गयीं पर अपने लम्बे राजनीति अनुभव के बावजूद डॉक्टरों से बातचीत का गतिरोध नहीं तोड़ पायीं

अंजन राय- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 14 सितम्बर। अनुभवों तथा चतुर राजनीतिज्ञ ममता बनर्जी ने, वर्तमान संकेत का समाधान ढूँढने के लिए आंदोलनरत जूनियर डॉक्टरों के केवल एक छोटे से ग्रुप को शाम को अपने घर बुलाकर डॉक्टरों के आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया।

उन्होंने हर तरह से युवा डॉक्टरों को लुभाने की कोशिश की, यहाँ तक कि उनके स्वास्थ्य के बारे में भारी चिंता भी व्यक्त की। चूँकि, इन दिनों शहर में लगातार बारिश हो रही है, मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों को "नहीं मींगने" की सलाह दी।

डॉक्टरों के केस को हैण्डल करने के राज्य सरकार के रवैये से भी जूनियर डॉक्टर नाखुश हैं। सरकार ने दावा किया है कि 29 लोग मरे हैं, जबकि, डॉक्टर इस दावे को गलत बता रहे हैं। इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए ममता बनर्जी के जो हातशा भरे प्रयास हैं। उनसे

उन्होंने अपने मनाने और मनुहार के सभी तरीके अपनाये, "चार्म" का पूरा उपयोग किया, पर, डॉक्टरों को तोड़ नहीं पायीं। अन्ततोगत्वा, मु.मंत्री ममता बनर्जी व आन्दोलनकारी डॉक्टरों की बातचीत इसलिये टूटी, क्योंकि, इस पर सहमति नहीं बनी कि मु.मंत्री के निवास पर आयोजित बातचीत व बैठक की वीडियोग्राफी कौन-कौन करेगा, केवल सरकारी वीडियोग्राफर या साथ में आए आन्दोलनकारी डॉक्टरों के वीडियोग्राफर।

सरकार किसी भी हालत में, आन्दोलनकारियों के वीडियोग्राफर को बैठक की वीडियोग्राफी करने की इजाजत नहीं देना चाहती थी। पता चलता है कि सरकार इस मामले में कितनी बुरी तरह से धिर चुकी है। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि राज्य की जनता को, मुख्यमंत्री के साथ

और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, आंदोलन कर रहे जूनियर डॉक्टरों के आंदोलन के संकेत का समाधान निकालने के लिए व्यक्तिगत प्रयास किया। वो आंदोलन स्थल पर गईं और आंदोलन कर रहे डॉक्टरों से सीधे बात की। उन्होंने डॉक्टरों को आश्वासन दिया कि वो उनकी वैध मांगों पर विचार करेंगी। उन्होंने डॉक्टरों से काम पर वापस आने को कहा। तथापि, डॉक्टरों ने अपनी इस मांग को दोहराया कि उनकी सभी मांगों में माननी होगी।

बाद में उन्होंने जूनियर डॉक्टरों को अपने आवास पर आने का निमंत्रण दिया और संकेत का समाधान निकालने के लिए बातचीत करने को कहा। शुरू में डॉक्टरों ने मांग की कि सभी 3.0 प्रतिनिधियों को मीटिंग में शामिल होने की अनुमति देनी होगी। तथापि, बाद में डॉक्टर 15 लोगों का प्रतिनिधिमंडल लाने की मामता बनर्जी की मांग से सहमत हो गए।

अशोक गहलोत को आलाकमान ने "लॉलीपॉप" दिया

रेणु मिश्रल- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 14 सितम्बर। बहुत लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस हाई कमान ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री को

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हरियाणा में कांग्रेस का वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। सूत्रों का कहना है कि इस मौके का फायदा उठाकर गहलोत बड़ा पद पाने की कोशिश करेंगे। लॉलीपॉप थमाया है और वो भी भूपेन्द्र सिंह हूडा के हस्तक्षेप के बाद, जिनके अशोक गहलोत के साथ बहुत निकट के (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)